प्रदीप कुमार

बनाम

भारत संघ एवं अन्य

(सिविल अपील सं. 9082/2012)

14 दिसंबर, 2012

(अल्तमास कबीर, सीजेआई, सुरिंदर सिंह निजार और जे. चेलामेश्वर, जे. जे.,)

ग्राहक कर और सेवा कर ट्राइब्यूनल सदस्य (रिक्रूटमेंट और सेवा की शर्तें) नियम, 1987

नियम 9 (2) - बार से सीधे नियुक्त न्यायिक सदस्य की सेवा की समाप्ति-चुनौती-अभिनिर्धारित: हस्तगत प्रकरण में, नियम 9(2) सुसंगत है जो उपबंधित करता है कि ऐसे मामले, जिनमें बार से सीधे नियुक्त किये गये न्यायिक सदस्य के मामलों में जब तक वह कन्फर्म नहीं हो जाता है। उसकी नियुक्ति बिना किसी कारण उपबंधित किये एक माह का नोटिस दिये जाने के पश्चात् किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। प्रत्यर्थी परिवीक्षा काल का आवश्यक समय पूरा कर चुका है-तीन साल की सर्विस अवधि के दौरान उसके परिवीक्षा अवधि बढाये जाने का कोइे आदेश पारित नहीं किया

गया था - इसलिए, विभाग से यह अपेक्षित था कि प्रत्यर्थी के प्रदर्शन के बारे में एक वर्ष की समाप्ति से उचित अवधि के भीतर निर्णय लें, -

निर्वहन का आदेश अधिवक्ताओं द्वारा की गई शिकायत के अनुसरण में सी.ई.एस.टी.ए.टी. एवं राष्ट्रपति द्वारा की गई रिपोर्ट पर आधारित था, इसलिये यह कलंकित करने वाला, दंडात्मक प्रकृति का था और इस तरह, कानूनी द्वेष से दूषित था-राष्ट्रपति, सी. ई. एस. टी. ए. टी. की रिपोर्ट में निहित आरोपों को पूरा करने का अवसर दिए बिना, इसे पारित नहीं किया जा सकता था- इसके अलावा, नियम 9 (2) के तहत आवश्यकतानुसार एक महीने का नोटिस देने की प्रक्रिया से बचने के लिए आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार, शक्ति के गलत प्रयोग से दूषित हो जाता है। निर्वहन के आदेश को खारिज किया जाता है। प्रत्यर्थी सभी परिणामी लाभों के साथ बहाल होने का हकदार है-प्रशासनिक कानून-

कानून में द्वेष-भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14 - शक्ति का गलत अभ्यास

सी.ए. सं. 9089/2012 में प्रत्यर्थी होने पर बार से सीधे सदस्य (न्यायिक), सीमा शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में नियुक्त होने पर 22.11.2006 को पदभार ग्रहण किया। उसे एक आदेश दिनांक 19.11.2009 का मिला जो पहले अपनी परिवीक्षा की अवधि दिनांक 21.11.2008 तक और फिर 21.11.2009 तक बढाये जाने का था। प्रत्यर्थी

ने 20.11.2009 को अपना इस्तीफा दे दिया। उस दिन उसे सेवा से छुट्टी देने का आदेश नियम 8 (3) के तहत सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर सेवा) नियम, 1987 जारी किया गया था। उत्तरदाता द्वारा ओ.ए. में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष उक्त आदेश को चुनौती दी गई एवं तर्क दिया कि बार के प्रतिनिधियों द्वारा की गई शिकायत के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था, जो उसके कोर्ट रूम में दिनांक 09.09.2009 को घटित हुई थी और परिणामीय रिपोर्ट दिनांक 18.11.2009 राष्ट्रपति, सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा भेजी गई। न्यायाधिकरण ने ओ.ए. को खारिज कर दिया लेकिन उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि प्रतिवादी ने तीन साल से अधिक की सेवा पूरी की एवं वह न्यायिक सदस्य है इसलिये नियम 9(2) के तहत सेवाऐ एक महीने का नोटिस दिए बिना समाप्त नही की जा सकती।

अपीलों का निपटारा करते हुए न्यायालय ने निर्धारित किया:

1.1 सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा का नियम 8 कर अपील न्यायाधिकरण सदस्य (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1987 एक परिवीक्षाधीन के निर्वहन का प्रावधान करता है। यह तीन की अवधि के भीतर काम करता है, जिन वर्षों के दौरान एक सदस्य को परिवीक्षाधीन जारी रखा जा सकता है। अन्तर्गत नियम 8 (3) के तहत बिना कोई कारण बताए परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी सदस्य को किसी भी समय

सेवा से छुट्टी दी जा सकती है। 1147-जी-एच, 1.2 नियम 9 सदस्यों की सेवा के प्रत्यावर्तन या समाप्ति की बात करता है। नियम 9 (1) उन सदस्यों से संबंधित है, जिन्हें पहले से ही केंद्र सरकार द्वारा सेवा में नियुक्त किया गया है। नियम 9 (2) के तहत न्यायिक सदस्य के मामले, तत्काल मामले में, सीधे बार से भर्ती, निर्धारित प्रक्रिया की पालना करना आवश्यक है। नियम 9 (2) यह प्रावधान करता है कि न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति के मामले में सीधे बार, जब तक कि उसकी पुष्टि नहीं हो जाती, उसकी नियुक्ति हो सकती है केंद्र सरकार द्वारा उसे एक महीने का समय देने के बाद बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त कर दिया जाता है।

नियम 9 (1) प्रावधान में यह तर्क है केन्द्र सरकार पद से भर्ती किये गये सदस्यों को उसके मूल पद पर वापस लाने में सक्षम बनाता है। बार से सीधे भर्ती किए गए न्यायिक सदस्यों को केन्द्र सरकार के पदो से भर्ती किए गए सदस्यों के बराबर रखने के लिये नियम 9 (2) में एक महीने के नोटिस का प्रावधान किया गया है। पैरा 5 और 10, 1148-ए-बी, डी-ई, एच; 1149-ए; 1153-ई,

1.3 मौजूदा मामले में, डिस्चार्ज के आदेश के बरकरार नहीं रखा जा सकता है क्योंकि यह प्रकृति में कलंकात्मक और दण्डात्मक है। यह रिकार्ड की बात है कि तीन साल की सेवा के दौरान प्रतिवादी की परिवीक्षा अवधि

बढाने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया था, उन्होनें 21.11.2007 को परिवीक्षा की अनिवार्य अवधि पूरी कर ली, इसलिए विभाग से यह अपेक्षा की गई कि वह एक वर्ष की समाप्ति से उचित अवधि के भीतर प्रतिवादी के प्रदर्शन के बारे में निर्णय लें। प्रतिवादी अपने कार्यों को दोषो या अपने प्रदर्शन के बारे में कोई औपचारिक या अनौपचारिक सूचना प्राप्त किये बिना सेवा में बना रहा। यह भी रिकार्ड की बात है कि प्रतिवादी की पुष्टि की प्रक्रिया 26.11.2007 को शुरू की गई थी और उसकी पुष्टि की लिए सर्तकता रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई थी, इसलिये यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादी का आरोप मुक्त होना कुछ अधिवक्ताओं द्वारा की गई शिकायत और अध्यक्ष सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आधारित नहीं है। पैरा 6 और 11-12, 1153-एफ एच, 1154 - ए, एफ-जी,

1989 (3) एस. सी. सी. 311 पी. शेर डॉ. बनाम भारत संघ और अन्य।

2.1 दिनांक 18.11.2009 को अध्यक्ष सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट मे स्पष्ट रूप से इंगित किया गया कि सेवा मुक्ति का आदेश जारी करने का कारण उसमें निहित था।

प्रतिवादी को आरोप मुक्त करने के फैसले और अपीलकर्ता की अदालत में बार के सदस्यों द्वारा की गई गड़बडी और जिसके बैंच छोडने एवं अपने चैम्बर में सेवानिवृत होने के बीच स्पष्ट रूप से एक जीवंत संबंध

है। दिनांक 18.11.2009 को तैयार की गई राष्ट्रपति की रिपोर्ट में कोई संदेह नहीं है कि उक्त घटना के आधार पर प्रतिवादी की अनसुनी निंदा की गई थी, राष्ट्रपति, सीईएसटीएटी की रिपोर्ट पर आधारित डिस्चार्ज का आदेश स्पष्टतः कंलकपूर्ण, दण्डात्मक प्रकृति का और कानूनी द्वेष से प्रभावित है और अपीलकर्ता को उक्त रिपोर्ट में निहित आरोपों को पूरा करने का अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जा सकता है। पैरा 12-13, 1154-जी; 1155-ए, ड्र एच

2.2 इसके अलावा, धारा 9(2) के तहत आवश्यक एक महीने का नोटिस देने की प्रक्रिया से बचने के लिये सेवा मे मुक्त करने का आदेश पारित किया गया है और दिनांक 19.11.2009 को आदेश पारित किया गया था, जिसमें प्रतिवादी की परिवीक्षा अवधि दिनांक 21.11.2007 से 21.11.2008 और आगे 21.11.2009 तक बढा दी गई थी। यह स्पष्ट रूप से अगले ही दिन यानि 20.11.2009 को छुट्टी का आदेश जारी करने के परोक्ष उद्देश्य से किया गया था। भारतीय संघ की कार्यवाही निसंदेह शक्ति का एक गलत अभ्यास है। मुक्ति का आदेश मनमाना है, और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। नतीजतन, इस न्यायालय का मानना है कि प्रतिवादी सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा मे बहाल होने का हकदार है। जिस अवधि के दौरान उसे सेवा से बाहर रखने के लिए मजबूर किया गया है, उस अवधि के दौरान वह पूरा बकाया वेतन पाने का हकदार होगा। पैरा 10,1148-ए-बी,डी-ई,एच,1149-ए,1153-ई

भारत संघ और अन्य बनाम महावीर सी. सिंघवी 2010(9) एससीआर 246 = 2010 (8) एससीसी 220-पर निर्भर

केस कानून संदर्भः

1989 (3) एस. सी. सी. 311 पर भरोसा से 11

2010 (9) एससीआर 246 पर भरोसा 12 के लिए

2010 (9) एससीआर 246

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 9082/2012

नई दिल्ली स्थित उच्च न्यायालय, के डब्ल्यू पी संख्या 98/2011 के निर्णय और आदेश दिनांक 27.07.2012 से।

के साथ

अपील संख्या 9089/2012

मुकुल रोहतगी, बी. एच. अपीलकत्र्ता की ओर से मार्लापल्ले, सौरभ कृपाल, भास्कर बैसल और निखिल जैन।

के. राधाकृष्णन, एस. वसीम ए. कादरी, चारुल सरीन और बी. कृष्ण प्रसाद- प्रत्यर्थी की ओर से।

न्ययालय का निर्णय सुनाया गया।।

सुरिंदर सिंह निज्जर, जे. ।

1. दोनों विशेष अनुमति याचिकाओं में अनुमति प्रदान की गई।

2. इस सामान्य आदेश द्वारा, हम उपरोक्त दोनो अपीलों का निपटान करने का प्रस्ताव करते हैं क्योंकि वे दोनों दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 27 जुलाई, 2012 को तय की गई रिट याचिका ख्सी, संख्या 98/2011 में दिए गए एक ही फैसले के खिलाफ हैं। 2012 की विशेष अनुमति याचिका संख्या 34671 से उत्पन्न अपील भारत संघ द्वारा विभिन्न कानूनी आधारों पर फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई है। उपरोक्त निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण इसके बाद इसे 'कैट' के रूप में संदर्भित किया गया है, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया है। जिसमें 9 दिसंबर, 2010 को 2009 के ओए नंबर 3544 को खारिज कर दिया गया था, जिसके तहत प्रतिवादी था सेवा से बर्खास्त. 2012 की विशेष अनुमति याचिका संख्या 27821 से उत्पन्न अपील प्रदीप कुमार द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जहां तक कि उक्त निर्णय उन्हें दी गई राहत को केवल पारित आदेश को रद्द करने की सीमा तक सीमित करता है। कैट और आदेश दिनांक 20 नवंबर, 2009, जिसके तहत उन्हें सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण सीईएसटीएटी , में सदस्य, के रूप में सेवा से मुक्त कर दिया गया था।

3. हम सबसे पहले सिविल अपील संख्या... पर विचार करेंगे जो भारत संघ द्वारा विचारर्थ 2012 की विशेष अनुमति याचिका संख्या 34671/2012 से उत्पन्न हुई है।

4. प्रतिवादी बीस वर्षों से अधिक समय तक कलकत्ता उच्च न्यायालय के साथ-साथ सीईएसटीएटी के समक्ष एक प्रैक्टिसिंग वकील था, जो मुख्य रूप से सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर मामलों से निपटता था। 22 अप्रैल, 2006 को वह सेस्टा में सदस्य (न्यायिक) पद के लिए चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए। विधिवत चयनित होने पर, उन्होंने 22 नवंबर, 2006 को सेस्टा में सदस्य (न्यायिक) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। सेस्टा के सदस्य की सेवा शर्तें सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और (सेवा कर), अपीलीय न्यायाधिकरण सदस्यों (भर्ती और सेवा की शर्तो)ं, द्वारा शासित होती हैं। , नियम 1987 (इसके बाद नियम के रूप में संदर्भित),। वर्तमान कार्यवाही में विवाद उपरोक्त नियमों के नियम 8 एवं नियम 9 (2) की व्याख्या तक सीमित है। उक्त नियम इस प्रकार हैंः-

> "नियम 8. परिवीक्षा - (1) सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा।
>
> (2) केंद्र सरकार परिवीक्षा की अवधि को एक बार में एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकती है ताकि कुल मिलाकर परिवीक्षा की अवधि तीन वर्ष से अधिक न हो।

(3) किसी सदस्य को परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय बिना कोई कारण बताए सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है।

नियम 9. सदस्यों की सेवा का प्रत्यावर्तन या समाप्ति। - (1) संघ या राज्य के तहत किसी भी पद से तकनीकी या न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति के मामले में, जब तक कि ऐसे व्यक्ति की पुष्टि नहीं हो जाती, केंद्र सरकार किसी भी समय उसे बिना कोई कार्यभार सौंपे उसके मूल पद पर वापस कर सकती है। कारण, उसे इस तरह के प्रत्यावर्तन के लिए एक महीने का नोटिस देने के बाद और यदि कोई तकनीकी या न्यायिक सदस्य अपने मूल पद पर वापस लौटना चाहता है, तो उसे केंद्र सरकार को एक महीने का नोटिस देना होगा

बशर्ते कि यदि ऐसा तकनीकी या न्यायिक सदस्य अपने मूल पद के प्रासंगिक नियमों के अनुसार पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है, तो ऐसी समाप्ति की एक महीने की सूचना देने के बाद बिना कोई कारण बताए केंद्र सरकार द्वारा किसी भी समय नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। ऐसा तकनीकी या

न्यायिक सदस्य इस्तीफा देना चाहता है, तो उसे केंद्र सरकार को एक महीने का नोटिस देना होगा।

(2) बार से सीधे न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्ति के मामले में, जब तक कि उसकी पुष्टि नहीं हो जाती, केंद्र सरकार द्वारा उसे ऐसी समाप्ति का एक महीने का नोटिस देने के बाद बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। यदि ऐसा न्यायिक सदस्य इस्तीफा देना चाहता है, तो उसे केंद्र सरकार को एक महीने का नोटिस देना होगा।

5. उपरोक्त नियमों के तहत, सेस्टा के सदस्य को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाता है, नियम 8(1) इसके अलावा, नियम 8(2) के तहत, परिवीक्षा की अवधि को एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालाँकि, परिवीक्षा की कुल अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। नियम 8(3) के तहत किसी सदस्य को परिवीक्षा अवधि के दौरान बिना कोई कारण बताए किसी भी समय सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। यह नियम तकनीकी या न्यायिक सदस्यों की परिवीक्षा अवधि को विनियमित करने के लिए एक सामान्य प्रावधान बनाता है, भले ही उनकी भर्ती का स्रोत कुछ भी हो। दूसरी ओर, नियम 9 (1) और (2), दो अलग-अलग स्रोतों से भर्ती किए गए तकनीकी या न्यायिक सदस्यों से

संबंधित है। नियम 9(1) उन सदस्यों से संबंधित है, जिन्हें केंद्र सरकार की सेवा में पहले से ही नियुक्त किया गया है। ऐसे सदस्यों के मामले में नियम 9(1) में एक प्रावधान किया गया है ताकि केंद्र सरकार बिना कोई कारण बताए उसे उसके मूल पद पर वापस भेज सके, जब तक कि ऐसे व्यक्ति की पुष्टि नहीं हो जाती। ऐसे प्रत्यावर्तन की एक माह की सूचना देकर ऐसे सदस्य को उसके मूल पद पर वापस भेजा जा सकता है। यदि ऐसा कोई सदस्य अपने मूल पद पर वापस जाना चाहता है, तो उसे केंद्र सरकार को एक महीने का नोटिस देना आवश्यक है। प्रावधान के तहत, ऐसे सदस्य की सेवाएं बिना कोई कारण बताए एक महीने का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती हैं, यदि वह अपने मूल पद के प्रासंगिक नियमों के तहत पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है। ऐसे सदस्य को एक महीने का नोटिस देकर इस्तीफा देने का समान अधिकार है। हालाँकि, हम केवल नियम 9(2) से चिंतित हैं जो यह प्रावधान करता है कि बार से सीधे न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति के मामले में, जब तक कि उसकी पुष्टि नहीं हो जाती, उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा बिना बताए किसी भी समय किसी भी कारण से उसे एक महीने का नोटिस देने के बाद समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार यदि न्यायिक सदस्य इस्तीफा देना चाहता है, तो उसे केंद्र सरकार को एक महीने का नोटिस देना आवश्यक है। नियम 8 स्पष्ट रूप से तीन वर्षों की अवधि के भीतर लागू होता है, जिसके दौरान एक सदस्य को परिवीक्षा पर जारी रखा जा सकता है। नियम 9(2) केवल उन मामलों में

लागू होगा जहां न्यायिक सदस्य को परिवीक्षा पर तीन साल की अधिकतम अवधि के बाद भी पुष्टि नहीं की गई है। नियम 9(2) तीन वर्ष की अवधि के भीतर लागू नहीं होगा। नियम 8 परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवामुक्त करने का प्रावधान करता है। नियम 9(2) सेवा समाप्ति की बात करता है। ऐसी परिस्थितियों में, यह प्रावधान है कि समाप्ति से पहले एक महीने का नोटिस दिया जाएगा। लेकिन यह प्रक्रिया तभी लागू होगी जब न्यायिक सदस्य तीन साल या उससे अधिक समय से सेवा में हो। अन्यथा नियम 8 में ही एक माह के नोटिस का प्रावधान किया गया होता। नियम 9(1) में प्रावधान का अंतर्निहित तर्क यह है कि केंद्र सरकार के पद से भर्ती किए गए सदस्य को उसके मूल पद पर वापस भेजा जा सके। बार से सीधे भर्ती किए गए न्यायिक सदस्यों को केंद्र सरकार के पदों से भर्ती किए गए लोगों के बराबर रखने के लिए नियम 9(2) में एक महीने के नोटिस का आवश्यक प्रावधान किया गया है। यदि न्यायिक सदस्य की पुष्टि नहीं होने पर तीन साल की अवधि के भीतर उसे बर्खास्त कर दिया जाता है, तो ऐसे किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी।

6. नियम 8 और 9 की उपरोक्त व्याख्या को ध्यान में रखते हुए, अब तथ्यों की जांच करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि 21 नवंबर, 2007 को या उसके तुरंत बाद परिवीक्षा की अनिवार्य अवधि के अंत में प्रतिवादी की परिवीक्षा अवधि बढ़ाने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। इसलिए, प्रतिवादी सदस्य न्यायिक के रूप में काम करता रहा। हालाँकि, उन्हें 19

नवंबर, 2009 को परिवीक्षा की अवधि बढ़ाने का एक आदेश पहले 21 नवंबर, 2008 तक और फिर 21 नवंबर, 2009 तक प्राप्त हुआ। 19 नवंबर, 2009 के पत्र की प्राप्ति के परिणामस्वरूप प्रतिवादी ने 20 नवंबर, 2009 को सदस्य न्यायिक, सीईएसटीएटी के पद से अपना इस्तीफा दे दिया। उसी तारीख को एक आदेश जारी किया गया जिसके तहत प्रतिवादी को सदस्य न्यायिक, सीईएसटीएटी के पद से सेवा से मुक्त कर दिया गया। उक्त आदेश नीचे पुनरू प्रस्तुत किया गया हैः-

एफ-नंबर-26/8/2006-एडी.आईसी

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

नई दिल्ली 20 नवंबर 2009

2009 का आदेश संख्या 5

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण सदस्य (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम 1987 के नियम 8(3) के अनुसरण में , राष्ट्रपति जी इसके द्वारा श्री पीके दास सीमा शुल्क उत्पाद एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में सदस्य (न्यायिक)। को तुरंत सेवा से पदमुक्त कर देते हैं।

2. राष्ट्रपति के आदेशानुसार तथा नाम से।

एसडी/-

(विक्टर जेम्स)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा मे,

श्री. पीके दास, सदस्य (न्यायिक)

सेस्टेट, वेस्ट ब्लॉक नंबर 2

आरके पुरम, नई दिल्ली

प्रतिलिपिः-

1. अध्यक्ष, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

2. रजिस्ट्रार, सीमा शुल्क उत्पाद एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

3. स्थापना अधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग नॉर्थ ब्लॉक।

4. वेतन एवं लेखा अधिकारी, राजस्व विभाग

5. अधिसूचना फ़ोल्डर

-एसडी-

(विक्टर जेम्स)

अवर सचिव, भारत सरकार

ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद 23 अक्टूबर, 2009 के पत्र द्वारा प्रतिवादी ने नियम 9(2) के तहत अपना इस्तीफा वापस ले लिया, जो कि एक महीने की निर्धारित अवधि के भीतर ही था।

7. अपनी सेवा की अवधि के दौरान प्रतिवादी ने सेस्टा के तीन अध्यक्षों, अर्थात् न्यायमूर्ति अभिचंदनानी, न्यायमूर्ति एसएन झा और न्यायमूर्ति आरएम खांडपारकर के अधीन कार्य किया था। प्रतिवादी का मामला यह है कि उसे सदस्य (न्यायिक), सेस्टा के रूप में सेवा के दौरान किसी भी राष्ट्रपति से कभी कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं मिली। वास्तव में, उन्हें वर्ष 2007 और 2008 में वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई थी। चूंकि, उन्हें कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं मिली थी, इसलिए प्रतिवादी ने मान लिया कि उन्हें सदस्य न्यायिक, सेस्टा के पद पर पुष्टि की जाएगी। लेकिन उन्हें गहरा सदमा और निराशा हुई, जब उन्हें 19 नवंबर, 2009 का आदेश मिला, जिसने उनकी परिवीक्षा अवधि पहले 21 नवंबर, 2008 तक और फिर 21 नवंबर, 2009 तक बढ़ा दी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रतिवादी का मामला यह है

कि इसमें 26 नवंबर, 2007 का एक नोट फ़ाइल संख्या 27/22/2005-एडी.-आईसी है। जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादी की पुष्टि की प्रक्रिया शुरू करने की कार्रवाई, जो 22 नवंबर, 2007 को होनी थी, एक नई फ़ाइल में शुरू की जाएगी। 23 जनवरी, 2008 को एक और नोटिंग है जिसमें प्रतिवादी और दो अन्य सदस्यों की एसीआर मांगी गई है। 6 जून, 2008 को सेस्टा के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एसएन झा ने राजस्व विभाग के सचिव को पत्र लिखकर प्रतिवादी सहित सेस्टा के कुछ सदस्यों की पुष्टि के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया। जहां तक प्रतिवादी का सवाल है, सतर्कता सेल ने भी अपने दृष्टिकोण से अपनी मंजूरी दे दी है।

8. हालाँकि, परिस्थितियाँ तब पूरी तरह से बदल गईं, जब अचानक 14 सितंबर, 2009 को प्रतिवादी को सेस्टा के अध्यक्ष से एक नोट प्राप्त हुआ, जिसके साथ बार के सदस्यों की शिकायत की एक प्रति संलग्न थी जो 9 सितंबर, 2009 को प्रतिवादी की अदालत में कथित तौर पर घटी एक घटना के बारे में की और उस घटना के बारे में रिपोर्ट देने का अनुरोध किया गया। सेस्टा के अध्यक्ष ने घटना के संबंध में 18 नवंबर, 2009 को एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, प्रतिवादी के आचरण के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियाँ शामिल थीं।

> "15. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब भी पार्टियों या उनके प्रतिनिधियों की ओर से अदालत में दुर्व्यवहार का

कोई कृत्य होता है, तो यह अनिवार्य रूप से पीठासीन अधिकारी के लिए होता है कि वह उचित नियंत्रण करे और उस कारण उत्पन्न होने वाले तनाव को कम करने का प्रयास करे और तुरंत चैम्बर में सेवानिवृत्त न हों। ऐसी स्थिति में अदालत से विरत रहना और उसे छोड़ देना तथा उसे सभी अदालती परिणामों के लिए खुला और स्वतंत्र छोड़ देना अदालत में अनुशासनहीनता को बढ़ावा देना है। केवल इसलिए कि पार्टियों के कुछ प्रतिनिधि बेंच के खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं या आरोप लगाने लगते हैं, अदालती कामकाज छोड़कर चैंबर में चले जाना उचित नहीं होगा। बल्कि पीठासीन अधिकारी को प्रशासनिक सूझबूझ से ऐसी स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास करना होगा। मौजूदा मामले में, पीठासीन अधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई प्रयास नहीं किया गया है।

प्रतिवादी का दावा है कि उसकी सेवाएं बार के प्रतिनिधियों द्वारा की गई शिकायत और अध्यक्ष, सेस्टा की रिपोर्ट के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में समाप्त कर दी गईं।

9. उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, प्रतिवादी ने 7 दिसंबर, 2009 को 2009 के व्। नंबर 3544 के माध्यम से ब्।ज् के समक्ष इसे चुनौती

दी। 9 दिसंबर, 2009 को व्। को ब्।ज् द्वारा खारिज कर दिया गया। कैट ने इस दलील को खारिज कर दिया कि प्रतिवादी को परिवीक्षा की एक वर्ष की अवधि पूरी होने पर पुष्टि की गई मानी जाएगी। किसी भी स्थिति में ऐसा लगता है कि प्रतिवादी ने शुरू में कुछ तर्कों के बाद और 2009 के ओए नंबर 1895 में सीएटी के फैसले पर विचार करने के बाद डीम्ड पुष्टिकरण के संबंध में विवाद को छोड़ दिया था - डॉ. विनीत सोढ़ी बनाम भारत संघ का फैसला 6 दिसंबर, 2010 को हुआ था। सीएटी प्रतिवादी की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि सेवा से बर्खास्तगी का आदेश दंडात्मक प्रकृति का था। कैट द्वारा यह माना गया कि भले ही बार के सदस्यों द्वारा की गई शिकायत के संबंध में अध्यक्ष, सीईएसटीएटी से रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, अंततः प्रतिवादी की बर्खास्तगी उसकी नौकरी की अनुपयुक्तता और कर्तव्य के असंतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर की गई थी। कैट ने यह भी देखा कि पूर्ण पैमाने पर कोई औपचारिक जांच नहीं की गई थी, बल्कि प्रतिवादी के असंतोषजनक प्रदर्शन के बारे में सक्षम प्राधिकारी के ध्यान में केवल तथ्य लाए गए थे। इन टिप्पणियों के साथ, व्। को खारिज कर दिया गया।

10. व्यथित प्रतिवादी ने 2011 की रिट याचिका ख्सी, संख्या 98 के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष आदेश को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने केवल नियम 8(3) और नियम 9(2) की व्याख्या पर रिट याचिका को अनुमति दी, हालांकि प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के विचार के

लिए चार विशिष्ट बिंदु उठाए थे। यह प्रस्तुत किया गया कि बर्खास्तगी के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह शक्ति के मनमाने प्रयोग में पारित किया गया था। इसे कानून में दुर्भावना का उत्पाद बताया गया। दूसरे, यह प्रस्तुत किया गया कि डिस्चार्ज आदेश प्रकृति में दंडात्मक था क्योंकि यह कलंकपूर्ण था और इसलिए, यह आवश्यक था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के तहत जांच की जानी चाहिए। तीसरा, यह प्रस्तुत किया गया कि संबंधित नियमों और इस मामले में उक्त नियमों के नियम 9(2) के तहत समाप्ति से पहले एक महीने का नोटिस देना आवश्यक है। वह नोटिस निश्चित रूप से नहीं दिया गया था और इसलिए, बर्खास्तगी गलत थी। चैथा, यह प्रस्तुत किया गया कि नियमों के नियम 8 के आधार पर प्रतिवादी को पुष्टिकृत माना जा सकता है। नियमों के नियम 8 और 9 की व्याख्या पर उच्च न्यायालय ने माना है कि चूंकि प्रतिवादी ने तीन साल से अधिक की सेवा पूरी कर ली थी और वह एक न्यायिक सदस्य था, इसलिए नियम 9(2) के तहत उसकी सेवाएं उसे एक महीने की सूचना दिए बिना समाप्त नहीं की जा सकतीं। हमारे विचार में उच्च न्यायालय द्वारा नियम 9(2) पर दी गई व्याख्या सही नहीं की है। बार से सीधे भर्ती किए गए न्यायिक सदस्य के मामले में, नियम 9(2) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है, यदि ऐसा सदस्य बिना पुष्टि किए तीन साल या उससे अधिक समय तक बना रहता है।

11. फिर भी सेवामुक्ति के आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यह प्रकृति में कलंकात्मक और दंडात्मक है। यह रिकॉर्ड की बात है कि तीन साल की सेवा के दौरान प्रतिवादी की परिवीक्षा अवधि बढ़ाने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया था। उन्होंने 21 नवंबर, 2007 को परिवीक्षा की अनिवार्य अवधि पूरी कर ली, इसलिए, विभाग से यह अपेक्षा की गई थी कि वह एक वर्ष की समाप्ति से उचित अवधि के भीतर प्रतिवादी के प्रदर्शन के बारे में निर्णय लेगा। यह भी रिकॉर्ड की बात है कि प्रतिवादी अपने काम में दोषों या अपने प्रदर्शन में किसी कमी के बारे में कोई औपचारिक या अनौपचारिक सूचना प्राप्त किए बिना सेवा में बना रहा। इस न्यायालय ने सुमति पी. शेरे डॉ. बनाम के यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य (1) के मामले मे एक परिवीक्षार्थी को प्रदर्शन में दोषों और कमियों के बारे में समय पर संचार करने के महत्व पर जोर दिया, ताकि वह अपने काम में सुधार के लिए आवश्यक प्रयास कर सके। काम में उसकी कमियों के बारे में संचार न करने से अनुपयुक्तता के आधार पर ऐसे कर्मचारी का कोई भी स्थानांतरण आदेश मनमाना हो जाएगा। निर्णय के पैराग्राफ 5 में, यह देखा गया हैः -

> "5. हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि मालिक और नौकर के रिश्ते में निष्पक्षता से कार्य करना एक नैतिक दायित्व है। कर्मचारी के काम के मूल्यांकन पर एक अनौपचारिक, यदि औपचारिक नहीं, लेन-देन होना चाहिए।

कर्मचारी को उसके काम में खामी और उसके प्रदर्शन में कमी के बारे में अवगत कराया जाना चाहिए। दोष या कमी कर्मचारी के साथ उदासीनता या अविवेक असावधानी के कारण हो सकता है, काम करने में असमर्थता के कारण नहीं। ऐसे मामलों में काम के मूल्यांकन का समय पर संचार कर्मचारी को सही रास्ते पर ला सकता है। ऐसे किसी भी संचार के बिना, हमारी राय में, अनुपयुक्तता के आधार पर कर्मचारी को आंदोलन आदेश देना मनमाना होगा। हमारी राय में, उपरोक्त टिप्पणियाँ इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पूरी तरह से लागू होती हैं।

12. यह भी रिकॉर्ड की बात है कि प्रतिवादी की पुष्टि की प्रक्रिया 26 नवंबर, 2007 को शुरू की गई थी। यह भी विवादित नहीं है कि उसकी पुष्टि के लिए सतर्कता रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई थी। इसलिए, भारत संघ के विद्वान वकील की इस दलील को स्वीकार करना मुश्किल है कि प्रतिवादी का आरोपमुक्त होना कुछ अधिवक्ताओं द्वारा की गई शिकायत पर आधारित नहीं है। 18 नवंबर, 2009 को अध्यक्ष, सेसटैट द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया कि सेवामुक्त करने का आदेश जारी करने का एकमात्र कारण उपरोक्त रिपोर्ट में निहित था। हमारी राय में भारत संघ

द्वारा पारित मुक्ति का आदेश स्पष्ट रूप से कानूनी द्वेष से दूषित था। यह स्पष्ट रूप से सेस्टा के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर स्थापित किया गया था। हमारी राय में यहां का विवाद पूरी तरह से इस न्यायालय के पहले के कई निर्णयों द्वारा कवर किया गया है, जिन पर भारत संघ और अन्य बनाम महावीर सी सिघवी के मामले में विचार किया गया है और पुनः पुष्टि की गई है। (2) ऐसी ही परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः-

"25. मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विभिन्न स्तरों पर एक तरफा जांच की गई थी। प्रमुख अधिकारियों द्वारा राय व्यक्त की गई और प्रतिवादी की दोषीता से संबंधित निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा गया जिन्होंने खुद को इस संबंध में आश्वस्त किया था। प्रतिवादी को सेवा से बर्खास्त करने का विवादित निर्णय केवल संदेह पर आधारित नहीं था। हालाँकि, यह सब प्रतिवादी की पीठ पीछे किया गया था और तदनुसार कथित कदाचार जिसके लिए प्रतिवादी की सेवाएँ समाप्त की गईं और समाप्त की गईं, वह केवल उक्त निर्णय का मकसद नहीं था बल्कि स्पष्ट रूप से इसकी नींव थी।

13. हमारी राय में, दिनांक 19 नवंबर, 2009 के आदेश द्वारा प्रतिवादी को बर्खास्तगी करने के निर्णय के बीच स्पष्ट रूप से एक जीवंत

संबंध है; प्रतिवादी की अदालत में बार के सदस्यों द्वारा की गई अशांति और उसका बेंच छोड़कर अपने चैंबर में चले जाना। राष्ट्रपति की रिपोर्ट में कोई संदेह नहीं है कि उपरोक्त घटना और 18 नवंबर, 2009 की सीईएसटीएटी अध्यक्ष की रिपोर्ट के आधार पर प्रतिवादी की अनसुनी निंदा की गई थी। बर्खास्तगी करने का आदेश जो राष्ट्रपति की रिपोर्ट पर आधारित है। स्पष्ट रूप से कलंकात्मक है और प्रतिवादी को राष्ट्रपति, सेस्टा की रिपोर्ट में निहित आरोपों को खण्डन करने का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जा सकता था। हम यहां महावीर सी. सिंघवी सुप्रा, के मामले में इस अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों पर ध्यान दे सकते हैंः-

> "46. जैसा कि हमारे सामने उद्धृत कुछ मामलों में माना गया है, यदि किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति के खिलाफ उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के आधार पर उसके खिलाफ निष्कर्ष निकाला जाता है और यदि वही आदेश की बर्खास्तगी नींव बनता है तो यह गलत होगा और खारिज किये जाने योग्य होगा। दूसरी ओर, यदि कोई जांच नहीं की गई या उस पर विचार नहीं किया गया और आरोप केवल एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सुनवाई के बिना उसे सेवामुक्त करने का आदेश पारित करने का एक मकसद था, तो वही मान्य होगा। हालाँकि, बाद वाला दृष्टिकोण इस मामले के तथ्यों से आकर्षित नहीं है।

14. इसके अलावा, हमारी यह भी राय है कि नियम 9(2) के तहत आवश्यक एक महीने का नोटिस देने की प्रक्रिया से बचने के लिए सेवामुक्त करने का आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त नियम ने सेस्टा के सदस्यों के बीच अंतर कर दिया है जो सेस्टा के सदस्यों के रूप में भर्ती होने से पहले केंद्र सरकार में काम कर रहे थे और बार से सीधे भर्ती किए गए न्यायिक सदस्य के बीच अंतर किया गया है। केंद्र सरकार की विभिन्न सेवाओं से भर्ती किए गए सदस्यों के मामले में, उनके मूल विभाग में प्रत्यावर्तन का प्रावधान किया गया है। उनके मामले में बिना कोई कारण बताए उन्हें मूल विभाग में वापस करने का भी प्रावधान किया गया है। हालाँकि, ऐसा केवल एक महीने का नोटिस देने पर ही किया जा सकता है। सीधे भर्ती किए गए न्यायिक सदस्य के मामले में नियम 9(2) यह विशेष रूप से प्रदान किया गया है कि तीन साल पूरे होने पर यदि न्यायिक सदस्य की पुष्टि नहीं हुई है, तो उसकी सेवाएं केवल एक महीने का नोटिस दिए जाने पर समाप्त की जा सकती हैं। इस प्रावधान से बचने के लिए, 19 नवंबर, 2009 को एक आदेश पारित किया गया, जिसमें प्रतिवादी की परिवीक्षा अवधि को 21 नवंबर, 2007 से 21 नवंबर, 2008 तक और आगे 21 नवंबर, 2009 तक बढ़ा दिया गया। यह स्पष्ट रूप से एक अप्रत्यक्ष उद्देश्य से जारी किया गया था। अगले ही दिन, यानी 20 नवंबर, 2009 को बर्खास्ती का आदेश भारतीय संघ की कार्रवाई निस्संदेह शक्ति का एक गलत अभ्यास है। आरोपमुक्त करने का आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 14

का पूरी तरह से उल्लंघन है , जो इसे शून्य बनाता है। उपरोक्त विवेचन को ध्यान में रखते हुए, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि भारत संघ द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका संख्या 34671/2012 पूरी तरह से योग्यता से रहित है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

15. यह अब हमें प्रदीप कुमार द्वारा दायर 2012 की विशेष अनुमति याचिका संख्या 27821 से उत्पन्न अपील पर लाता है, जिसमें बहाली की राहत और पूर्ण वेतन सहित परिणामी लाभ देने का दावा किया गया है। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी की रिट याचिका को केवल इस आधार पर अनुमति दी थी कि नियम 9(2) का उल्लंघन हुआ है, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि शक्ति का गलत प्रयोग, कलंकपूर्ण होने के कारण बर्खास्ती का आदेश दूषित हो गया था। और प्रकृति में दंडात्मक है और इस तरह के आदेश को कानून में कायम नहीं रखा जा सकता है। हमारी राय में, बर्खास्ती का आदेश मनमाना है और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। नतीजतन, हम मानते हैं कि अपीलकर्ता - प्रदीप कुमार सेवा में बहाल होने का हकदार है। जिस अवधि के दौरान उसे सेवा से बाहर रहने के लिए मजबूर किया गया है, उस अवधि के दौरान वह पूरा बकाया वेतन पाने का हकदार होगा। भारत संघ को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के दो महीने की अवधि के भीतर उक्त प्रदीप कुमार को सभी परिणामी लाभ जारी करने का निर्देश दिया जाता है।

16. इन टिप्पणियों के साथ, भारत संघ द्वारा विशेष अनुमति याचिका से उत्पन्न 2012 की सिविल अपील संख्या 9089 ख्सी, 2012 की संख्या 34671 के रूप में दायर अपील को खारिज कर दिया जाता है और विशेष अनुमति से उत्पन्न 2012 की सिविल अपील संख्या 9082 को खारिज कर दिया जाता है। प्रदीप कुमार द्वारा दायर याचिका (सी) संख्या 27821/2012 स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी चेतन कुमार गोयल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।